



भविष्य के लिए तैयार कार्यबल: कुशल भारत की ओर बढ़ते कदम

29 अप्रैल, 2026

मुख्य बातें

- आर्थिक समीक्षा 2025-26 रोजगार-केंद्रित कौशल विकास पहलों के महत्व को दर्शाता है, जो कौशल अंतर को पाटने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हैं।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में कौशल विकास को एक बहु-क्षेत्रीय (क्रॉस-सेक्टरल) प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष पहलें शामिल हैं।
- प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:
 - तकनीकी वस्त्रों में मूल्यवर्धन के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स।
 - खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए चार दूरबीन बुनियादी ढांचा सुविधाओं का उन्नयन या स्थापना।
 - अकादमिक, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद की शुरुआत।
 - खेलो इंडिया मिशन पर्यटन से जुड़ी आतिथ्य शिक्षा और भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा।

कौशल भारत के विकास इंजन को मजबूती

भारत इस समय एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मोड़ पर है। दुनिया के सबसे युवा कार्यबलों में से एक होने के कारण, देश में उच्च उत्पादकता हासिल करने और उपभोक्ता मांग को बढ़ाने की व्यापक क्षमता मौजूद है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में इस पर जोर दिया गया है कि रोजगार-केंद्रित कौशल पहलकदमियां न केवल उत्पादकता में सुधार लाती हैं, बल्कि कौशल अंतराल को भरते हुए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर भी प्रदान करती हैं। ऐसी योजनाएं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देकर सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाती हैं, जिससे समावेशी श्रम बाजारों तक अधिक समतामूलक पहुंच सुनिश्चित होती है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े श्रम बाजार की स्थिरता को इंगित करते हैं, जिसमें विशिष्ट मौसमी उतार-चढ़ाव दिखते हैं। फरवरी 2026 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 55.9 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान श्रम बाजार में

महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला, जिसमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट शामिल है।

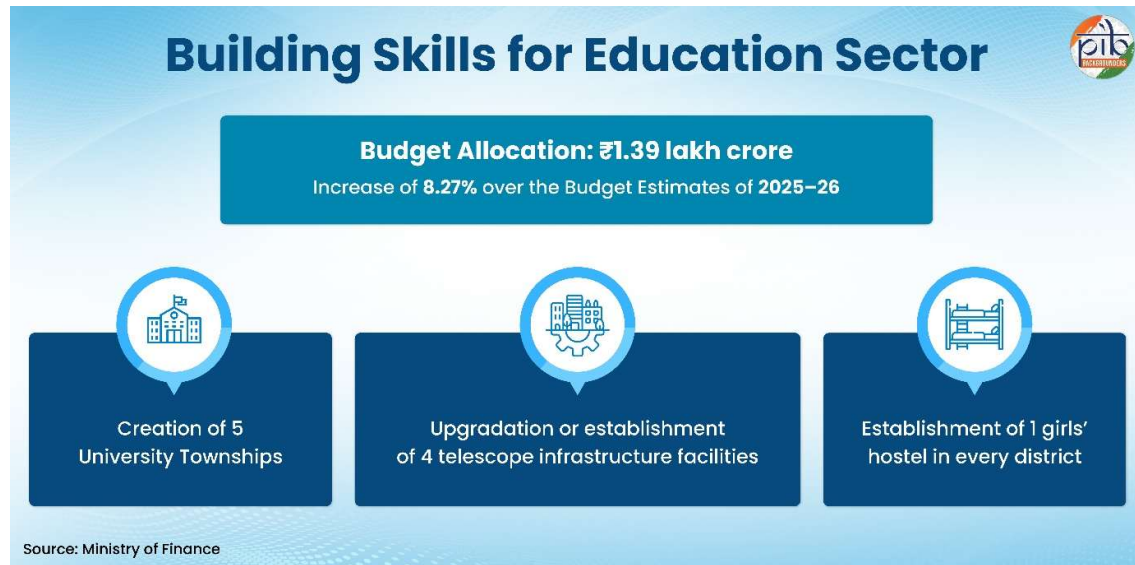
युवा आबादी की संभावनाओं और कौशल विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में कौशल विकास को एक बहु-क्षेत्रीय प्राथमिकता के रूप में रखा है। हाल की पहल सरकार की उस निरंतर नीतिगत प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की युवा पीढ़ी मात्र संख्या में बड़ी न हो, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य में गंभीर और प्रभावशाली योगदान देने के लिए तैयार और सशक्त हो।

बजट में कौशल पर फोकस: अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2026-27 में संस्थागत क्षमता का विस्तार करने, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उभरती उद्योग की मांगों के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए लक्षित पहल की गई है। इन उपायों का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत में रोजगार क्षमता बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर पैदा करना है।

शिक्षा

भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता को साकार करने के लिए कुशल और शिक्षित आबादी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2026-27 1.39 लाख करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ शिक्षा क्षेत्र को और गति प्रदान करता है। यह 2025-26 के बजट अनुमानों से 8.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आवंटन पहुंच का विस्तार करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के साथ अधिक संरेखित करने पर केंद्रित है।



इसके लिए बजट में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों, कौशल केंद्रों और आवासीय परिसरों की मेजबानी के लिए प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गलियारों के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण।
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ)/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 बालिका छात्रावास की स्थापना। यह उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में विस्तारित शैक्षणिक और प्रयोगशाला घंटों से उत्पन्न होने वाली पहुंच और प्रतिधारण चुनौतियों का समाधान करने के लिए घोषित किया गया है।
- इमर्सिव अनुभवों के माध्यम से खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और कॉसमॉस-2 तारामंडल सहित 4 टेलीस्कोप बुनियादी ढांचा सुविधाओं का उन्नयन या स्थापना।

कपड़ा और परिधान

भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ~2 प्रतिशत, विनिर्माण जीवीए में लगभग 11 प्रतिशत और निर्यात में 8.63 प्रतिशत का योगदान देता है। विश्व स्तर पर छठे सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक के रूप में, यह क्षेत्र एमएसएमई समूहों में मजबूत उपस्थिति और महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ 45 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का समर्थन करता है। उद्योग के बुनकरों और कारीगरों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, बजट में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं:

- प्राकृतिक, मानव निर्मित और नए युग के रेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना।
- पूंजीगत सहायता, उन्नत मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण अवसंरचना के माध्यम से पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना।
- मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करने और बुनकरों और कारीगरों को केंद्रित, आय-बढ़ाने वाली सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम।
- विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्रों और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल।
- समर्थ 2.0 संरचित उद्योग-अकादमिक साझेदारी के माध्यम से कपड़ा कौशल इसोसिस्टम का आधुनिकीकरण और उन्नयन करेगा।

मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ): कारखानों में बने फाइबर, या तो प्राकृतिक स्रोतों जैसे सेल्यूलोज (जैसे, रेयान) या रसायनों (जैसे, पॉलिएस्टर) से, प्राकृतिक फाइबर से मेल खाने या सुधारने के लिए बनाए जाते हैं।

नए जमाने के फाइबर: आधुनिक, अभिनव फाइबर जैसे कमल रेशम, बांस फाइबर, या स्मार्ट वस्त्र जो पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ या विशेष कार्यात्मक विशेषताएं हैं।

- **मेगा टेक्सटाइल पार्क** जो विशेष रूप से तकनीकी वस्त्रों में निर्माण पैमाने, दक्षता और मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- **महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल** उन्नत कौशल, गुणवत्ता आश्वासन और वैश्विक ब्रांडिंग लिंकेज के माध्यम से खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए

स्वास्थ्य

जनसांख्यिकीय बदलाव, बढ़ते गैर-संचारी रोगों और कुशल पेशेवरों की वैश्विक मांग के कारण भारत की आबादी की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं एक कुशल और विस्तारित स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं। इस संबंध में, बजट में संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा का विस्तार और सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से तीन वर्षों में 980 करोड़ रुपए का चरणबद्ध परिव्यय निर्धारित किया गया है। बजट की प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल उन्नति के लिए रणनीति) के माध्यम से संस्थानों का निर्माण और उन्नयन। इस कार्यनीति में 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (एनआईपीईआर) की स्थापना, 7 मौजूदा एनआईपीईआर का उन्नयन, 1,000 से अधिक नैदानिक परीक्षण स्थलों का सृजन और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का सुदृढीकरण शामिल है।
- मौजूदा संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) संस्थानों का उन्नयन और निजी और सरकारी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों की स्थापना। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ सहित 10 चयनित विषयों को शामिल किया गया है। अगले 5 वर्षों में कुल 100,000 एएचपी भी जोड़े जाएंगे।
- वृद्धावस्था और संबद्ध देखभाल सेवाओं को कवर करते हुए एक मजबूत देखभाल इकोसिस्टम का गठन। इसमें बहु-कुशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कार्यक्रमों का विकास शामिल है, जिसमें मुख्य देखभाल और संबद्ध कौशल, जैसे कि कल्याण, योग और चिकित्सा और सहायक उपकरणों के संचालन को शामिल किया गया है। आने वाले वर्ष में 1.5 लाख देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- चिकित्सा पर्यटन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी शुरू की जाएगी, जो निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी। ये हब स्वास्थ्य परिसरों को एकीकृत करेंगे जो चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं को जोड़ते हैं। उनके पास आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र और निदान, देखभाल के बाद और पुनर्वास के लिए बुनियादी ढांचा होगा। ये हब डॉक्टरों और एएचपी सहित स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के विविध अवसर प्रदान करेंगे।

Skilling Initiatives in Health & AYUSH



HEALTH

- Creation & upgradation of Institutes via **Biopharma SHAKTI**
- Upgradation & establishment of **AHPs Institutions**
- Development of variety of **NSQF aligned programmes**
- Scheme to support States in establishing **5 Regional Medical Hubs**

AYUSH

- Establishment of 3 new **All India Institutes of Ayurveda (AIIA)**
- Upgradation of **AYUSH pharmacies and Drug Testing Labs**
- Upgradation of the **WHO Global Traditional Medicine Centre in Jamnagar**

AHPs: Allied Health Professionals
NSQF: National Skill Qualification Framework
AIIA: All India Institutes of Ayurveda

Source: Ministry of Finance



आयुष

भारत के आयुष क्षेत्र को वैश्विक मान्यता मिल रही है। योग और आयुर्वेद निवारक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में उभर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 आयुष मंत्रालय के लिए 4,408 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आयुष क्षेत्र को और मजबूत करने और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित पहलों को रखा गया है:

- शिक्षा, नैदानिक सेवाओं और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों (एआईआईए) की स्थापना;
- प्रमाणन इकोसिस्टम के उच्च मानकों और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुष फार्मसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन;
- पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन।

पशुधन

पशुधन ग्रामीण सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। यह **कृषि आय में** खासकर गरीब और सीमांत परिवारों के लिए **लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। 6,153 करोड़ रुपए** के बजट आवंटन के साथ, केंद्रीय बजट 2026-27 आय विविधीकरण, पोषण सुरक्षा और रोजगार सृजन में क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

इसके अलावा, पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता को 20,000 से अधिक तक बढ़ाने के लिए, केंद्रीय बजट में भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा के साथ निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और पैरा-वेट कॉलेजों, अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना में सहायता के लिए ऋण-आधारित पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना की शुरुआत की गई है।

ऑरेंज इकोनॉमी

रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा से प्रेरित ऑरेंज इकोनॉमी आधुनिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर, रचनात्मक उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 0.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं, जिसका पर्यटन और शहरी सेवाओं में मजबूत प्रभाव पड़ता है। भारत में, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र, जिसका मूल्य 2024 में लगभग 2.5 ट्रिलियन है, के सालाना लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2027 तक लगभग 3.06 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा।

उच्च विकास वाले रचनात्मक क्षेत्रों में प्रतिभा पाइपलाइन को मजबूत करने के लिए, बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने पर जोर दिया गया है। एवीजीसी क्षेत्र को 2030 तक लगभग 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है, इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक चरण की रचनात्मक क्षमता का निर्माण करना, उद्योग-अनुरूप कौशल को बढ़ाना और वैश्विक डिजिटल सामग्री उत्पादन में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है।

डिजाइन

भारतीय डिजाइन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और सभी क्षेत्रों में कुशल डिजाइन पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है। डिजाइन शिक्षा को मजबूत करने और इस विकास का समर्थन करने के लिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित होने जा रहा है।

पर्यटन

पर्यटन निर्यात, रोजगार और भारत के वैश्विक सांस्कृतिक पदचिह्न का एक उच्च प्रभाव वाला चालक बना हुआ है। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.22 प्रतिशत का योगदान दिया, जो पूर्व-महामारी के स्तर के करीब है। इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से अनुमानित 8.46 करोड़ नौकरियों का समर्थन किया, जो देश में कुल रोजगार का लगभग 13.3 प्रतिशत है। केंद्रीय बजट 2026-27 लक्षित संस्थागत और कौशल-आधारित पहलों के माध्यम से इस गति को आगे बढ़ाता है:

- राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करके राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना। यह आतिथ्य शिक्षा मानकों को मजबूत करते हुए शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेगा।

- भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से विकसित 12 सप्ताह के हाइब्रिड पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 पर्यटक गाइडों के कौशल को बढ़ाने के लिए एक पायलट योजना विकसित की गई है।
- सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत स्थलों का डिजिटल रूप से दस्तावेजीकरण करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जिससे शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, सामग्री निर्माताओं और प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

खेल

केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है, जिसमें कुल आवंटन में 1,133 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह कदम भारत को 2036 तक शीर्ष 10 खेल देशों और 2047 तक शीर्ष 5 खेल देशों में रखने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मंत्रालय का आवंटन 2025-26 में 3,346 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) हो गया है।

उच्च आवंटन से केंद्र प्रायोजित खेल और युवा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करने की उम्मीद है, जिसमें एथलीट विकास पहल, युवा जुड़ाव कार्यक्रम, कोचिंग और सहायता प्रणाली, खेल विज्ञान का एकीकरण और खेल बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।



इसी के आधार पर, बजट में खेल क्षेत्र को व्यापक रूप से मजबूत करने के लिए **खेलो इंडिया मिशन** का शुभारंभ शामिल है। यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा:

- एक एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, जो मूलभूत, मध्यवर्ती और अभिजात स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित है;
- कोचों और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित विकास;
- खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण;
- खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और एथलीटों के लिए मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग; तथा
- प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल के बुनियादी ढांचे का विकास।

नीति समर्थन कौशल की मजबूती

सरकार ने हमेशा एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए प्रमुख कौशल पहलों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। ये कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता संवर्धन और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ में, उनका लक्ष्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग की उभरती जरूरतों के साथ कौशल विकास को संरेखित करना है।

स्किल इंडिया मिशन

2015 में शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम), प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। मिशन देश भर में समाज के सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित करता है, और कामकाजी उम्र की आबादी के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मिशन के तहत, निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवी),
- जैन शिक्षण संस्थान (जेएस),
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस),
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

Performance of Skill India Mission



PMKVY 4.0



27.74 lakh candidates trained (as on 31 March 2026)

Jan Shikshan Sansthan



36.48 lakh+ beneficiaries have been trained (until 31st March 2026)

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)



54.41 lakh+ apprentices engaged across sectors (until 31st March 2026)

Craftsmen Training Scheme (CTS)



14.70 lakh enrolled in FY 2025-26; up by 17.5% w.r.t. FY 2022-23

Source : Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)/पीएमकेवीवाई 4.0:** यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख अल्पकालिक कौशल पहल है। अपने चार चरणों के दौरान, यह एक पायलट प्रोत्साहन-आधारित प्रमाणन पहल से बड़े पैमाने पर, मांग-संचालित और परिणाम-उन्मुख कौशल इकोसिस्टम की ओर आगे बढ़ा है। इसके चौथे चरण अर्थात पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग के नेतृत्व वाले क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कई पाठ्यक्रम सीधे औद्योगिक परिसर के भीतर दिए जाते हैं, जिसमें नियोक्ता इकोसिस्टम से प्राप्त प्रशिक्षकों के साथ होता है। प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:
 - पीएमकेवीवाई 4.0 ने 31 मार्च 2026 तक 36 राज्यों और 737 जिलों को कवर करते हुए 38 क्षेत्रों में 27.24 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।
 - 1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2026 के बीच, 34 राज्यों और 737 जिलों में 10.91 लाख से अधिक उम्मीदवारों को आईटी-आईटीईएस, एयरोस्पेस और विमानन, कृषि, रबर, चमड़ा, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया।

- एआई, उद्योग 4.0, हरित नौकरियों और डिजिटल सेवाओं सहित उभरते क्षेत्रों में रोजगार क्षमता में सुधार के लिए 69 अनुकूलित पाठ्यक्रम और 154 भविष्य-कौशल नौकरी भूमिकाएं शुरू की गई हैं।
- 31 मार्च, 2026 तक 16,900 से अधिक संस्थान पीएमकेवीवाई 4.0 को लागू कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों और आईटीआई में 6,800 से अधिक स्किल हब शामिल हैं।
- **जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस):** शुरू में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में शुरू किए गए जेएसएस योजना का उद्देश्य सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान के साथ पंजीकृत समितियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी को अनौपचारिक मोड में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह गैर-साक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए समावेशी, समुदाय-आधारित कौशल को बढ़ावा देता है।

इसमें हासिल की गई प्रगति इस प्रकार है:

- 2018 से 31 मार्च 2026 तक कुल 36,48,692 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है
- पाठ्यक्रम स्थानीय मांग के अनुरूप हैं जिनमें सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं शामिल हैं।
- 31 मार्च 2026 तक 26,720 जनजातीय लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 26,519 को प्रशिक्षित किया गया है।
- कौशल विकल्पों में विविधता लाने के लिए, जेएसएस के तहत एनएसक्यूएफ स्तर 3, 3.5 और 4 पर 32 नए एनसीवीईटी-अनुमोदित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- दिसंबर 2024 से, जेएसएस उत्पादों का विपणन उद्यमकार्ट पोर्टल पर किया जाता है, जो कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस):** अगस्त 2016 में शुरू की गई यह योजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण, एनएपीएस 2.0 में लागू की जा रही है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है जिससे प्रशिक्षुता इकोसिस्टम मजबूत होता है और हितधारकों को समर्थन सहायता प्रदान की जाती है। अप्रेंटिसशिप "सीखते समय कमाएं" और उद्योग-केंद्रित कौशल विकास के लिए एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। सरकार एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में 25 प्रतिशत वजीफा (1,500 रुपए प्रति माह तक) का योगदान देती है।
 - 2016 से 31 मार्च, 2026 तक ऑटोमोटिव, आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 54.41 लाख से अधिक प्रशिक्षु लगे हुए हैं
 - वित्त वर्ष 2025-26 में, लगभग 12.35 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, लगभग 6.42 लाख प्रशिक्षुओं ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपना ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण पूरा किया।

- सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया सीओपी (प्रवीणता का प्रमाणपत्र), उन प्रशिक्षुओं के लिए एक अतिरिक्त मान्यता है जो पूरी अवधि और व्यावहारिक मूल्यांकन पूरा करते हैं। 31 मार्च, 2026 तक, 67,711 प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।
- 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 40.10 लाख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लेनदेन के माध्यम से 562.75 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की गई।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में कुशल श्रमिकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 1950 में सीटीएस शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाना और शिक्षित युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करके बेरोजगारी को कम करना है।





1. सीटीएस के तहत, देश भर में 14,688 आईटीआई (सरकारी - 3,345 और निजी - 11,343) के माध्यम से 169 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. मार्च 2026 तक, कुल 14 सीटीएस पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं और तीन साल की अवधि में 22 मौजूदा पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है। ये पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
3. आईटीआई में नामांकन वित्त वर्ष 2022-23 में 12.51 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 14.70 लाख हो गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)

आईटीआई भारत में दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा की रीढ़ हैं। इन्हें उद्योग में कुशल कर्मियों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

Institutional Capacity Building & ITI Reforms



	2014	2025
 ITIs Established	9,977	14,688
 NSTIs	25	33
 ITIs Enrollment	9.5 Lakh	14.7 Lakh
 IToTs	11	120

Source: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

ITIs: Industrial Training Institutes
NSTIs: National Skill Training Institutes
IToTs: Institutes for Training of Trainers

इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन) को अक्टूबर 2025 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 60,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरु किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और आधुनिक उपकरणों के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन।
- क्लस्टरों के सह-स्वामित्व और सह-प्रबंधन के लिए एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) के साथ विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की स्थापना।
- श्रम बाजार की मांग के आधार पर पाठ्यक्रमों का परिचय और नया डिजाइन, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ उन्नत उच्च मांग वाले पारंपरिक ट्रेडों शामिल हैं।
- हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य सहित कई राज्य अपनी मूल शक्ति के आसपास 1,000 आईटीआई के उन्नयन का सह-निर्माण कर रहे हैं।
- वैश्विक भागीदारी के साथ कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना) की क्षमता में वृद्धि।

निष्कर्ष

भारत का कौशल इकोसिस्टम इस समय समन्वित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-उन्मुख ढांचे के साथ एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 इस परिवर्तन को गति देने के लिए क्षेत्र-

विशिष्ट कौशल कार्यक्रमों को बुनियादी ढांचे के विकास के साथ एकीकृत करता है। इसमें आईटीआई का उन्नयन, पीएमकेवीवाई 4.0, पीएम-सेतु, एनएपीएस और अन्य पहलों को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य कौशल मूल्य श्रृंखला में पैमाने, गुणवत्ता, पारदर्शिता और उद्योग के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाना है।

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के प्रयासों के तहत, सरकार मांग आधारित प्रशिक्षण, परिणाम-केंद्रित दृष्टिकोण और समावेशी पहुंच को प्राथमिकता दे रही है। स्वास्थ्य सेवा, देखभाल अर्थव्यवस्था, एवीजीसी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कौशल को उपयुक्त रूप से संरेखित करते हुए नीतिगत ढांचा मानव पूंजी को मुख्य विकास कारक के रूप में स्थापित कर रहा है। समग्र रूप से, भारत का भविष्य-उन्मुख और मजबूत कौशल इकोसिस्टम न केवल उत्पादकता को बढ़ावा देता है, बल्कि औपचारिकता और समावेशन को भी तेज करता है। यह देश की जनसांख्यिकीय क्षमता को व्यापक और सतत विकास में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

संदर्भ

वित्त मंत्रालय

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>
https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

श्रम और रोजगार मंत्रालय

<https://eshram.gov.in/indexmain>

कपड़ा मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208051®=6&lang=1>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221616®=3&lang=2>

आयुष

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221910®=3&lang=2>

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221788®=3&lang=2>

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221825®=6&lang=1>

शिक्षा मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221734®=3&lang=1>

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221706®=3&lang=2>

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200373®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223182®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2217881®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197057®=3&lang=1>

<https://dsde.uk.gov.in/apprenticeship-training-scheme/>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236969®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149336®=3&lang=2>

आईटीआई, लाला हंस राज गुप्ता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

<https://itilhrg.delhi.gov.in/itilhrg/craftsmen-training-scheme-cts>

नीति आयोग

https://niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/ITI_Report_02022023_0.pdf

आईबीईएफ

<https://www.ibef.org/government-schemes/skill->

<india#:~:text=Onप्रतिशत20Julyप्रतिशत2015प्रतिशत2Cप्रतिशत202025प्रतिशत2Cप्रतिशत20the,Hyderababdप्रतिशत20andप्रतिशत20Chennaiप्रतिशत20wereप्रतिशत20launched>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240676®=3&lang=2>

पीआईबी मुख्यालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2228572®=3&lang=1>

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/बीयू/एचबी